P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-5* ISSUE-3* June - 2020
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

छत्तीसगढ़ राज्य में दुग्ध उत्पादन की संभावनाएं

Chances of Milk Production in Chhattisgarh State

Paper Submission: 10/06/2020, Date of Acceptance: 20/06/2020, Date of Publication: 25/06/2020

काव्या जैन
शोध छात्रा
शा.दिग्विजय स्वषासी
स्नातकोत्तर महाविद्यालय
राजनांदगांव (छ.ग.) भारत

ए.एन.माखीजा
स्हायक प्रध्यापक,
वाणिज्य विभाग,
शास.शिवनाथ विज्ञान
महाविद्यालय,
राजनांदगांव (छ.ग.) भारत

सारांश

राज्य में पशुधन का उत्पादन लगातार बढ़ते जा रहा है । वर्ष 2019 सितम्बर तक वार्षिक दुग्ध उत्पादन दर लगभग 7.6% हो गयी है । जो पूर्व वर्षो से लगभग 3.8% वार्षिक वृद्धि राष्ट्रीय स्तर पर पहुॅच गयी है। इसका मुख्य कारण है राज्य में डेयरी उद्योग को राज्य शासन द्वारा लगातार बजटीय प्रावधानो का बढ़ाना एवं विशेष ध्यान दिया जाना है। राज्य में जितना दूध उत्पादन किया जाता है वह शहरों एवं जिला स्तर या तहसील स्तर पर उपभोग कर दिया जाता है केवल 5 लाख लीटर दूध बाजार में पहुॅच पाता है।

Livestock production in the state is continuously increasing. By the year 2019 September, the annual milk production rate has been almost 7.96. Which has reached a national level of about 3.98% from previous years. The main reason for this is that the dairy industry in the state has to constantly increase budgetary provisions and special attention is given by the state government. The milk produced in the state is consumed at the cities and district level or tehsil level, only 5 lakh liters of milk can reach the market.

मुख्य शब्द : दुग्ध व्यवसाय , कृषि व्यवसाय , डेयरी व्यवसाय , परियोजनाएं पशु चिकित्सालय, गौपालन एवं गौशाला प्रबंधन ।

Milk Business, Agribusiness, Dairy Business, Projects Veterinary Hospital, Cow rearing and Cowshed Management

प्रस्तावना

भारत विश्व के अन्य दूध उत्पादक देशों में अग्रणी हैं आज हमारे देश में 79 करोड टन दूध उत्पादन हो रहा हैं। इसका मुख्य कारण बढ़ती हुई उत्पादक पशुओं की संख्या एवं कृषि की आधुनिक पद्धति है कृषि के विकास से ही पशुपालन एवं दुग्ध व्यवसाय की उन्नति संभव है। दुग्ध व्यवसाय एवं कृषि व्यवसाय एक दूसरे के पूरक व्यवसाय है, यदि देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना है तो दुग्ध व्यवसाय को साथ में अपनाना होगा, क्योंकि यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसके द्वारा देश की आर्थिक स्थिति में सुधार विषम परिस्थितियों जैसे आकाल, प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि, अल्पवर्षा, आदि के समय हो सकता है तथा जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन बन सकता हैं। मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए दुग्ध व्यवसाय वरदान साबित हो सकता है। इसके अलावा दुग्ध उत्पादन स्वरोजगार का सबसे कम लागत वाला व्यवसाय है। जो कि बेरोजगारी, भूखमरी, निर्धनता को दूर करने में सहायक हो सकता हैं। इसलिए यदि छत्तीसगढ़ में धान आधारित फसल पद्धति के साथ दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाए तो यहां के गौशालाओं, किसानों, ग्रामीण, बेरोजगार एवं पढ़े लिखे नवयुवकों के लिए वरदान साबित हो सकता है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. छ.ग.राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु योजना बनाना ।
2. राज्य में गौवंश एवं भैसवंशीय पशुओं की जनसंख्या तथा विकासक्रम का पता लगाना।
3. गौवंश संरक्षण एवं संर्वधन हेतु गौशाला का सुदृढ़ीकरण ।
4. पशु चिकित्सा एवं पशुओं के आहार की स्थिति का पता लगाना ।
5. राज्य में दुग्ध उत्पादन के उपभोग की दर ज्ञात करना ।

छत्तीसगढ़ राज्य में दुग्ध उत्पादन की संभावनाएं

छ.ग. में डेयरी व्यवसाय के लिए अत्यधिक संभवनाएं हैं, क्योकि यहां कि जलवायु व भौगोलिकता उपयुक्त है । इसका उचित उपयोग तब हो सकता है जब वैज्ञानिक परियोजना बनाई जायें। अभी तक जितनी भी योजनाएं बनी उनका उचित परिपालन नहीं हुआ क्योंकि मध्य प्रदेश एक वृहद राज्य था जिनमें

परियोजनाओं का उचित लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों को नहीं मिल पा रहा था। यह सौभाग्य की बात है कि हमें नया राज्य मिला एवं इसके बाद छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में डेयरी व्यवसाय को बढ़ाने में बहुत सफलता मिली एवं वर्तमान में छत्तीसगढ़ में डेयरी व्यवसाय देश में सातवें स्थान पर हैं। इसका मुख्य कारण यह है राज्य सरकार द्वारा सन् 2001 से 2019 तक 1.45 करोड़ की प्रतिवर्ष बढ़ोतरी की गई जिसमें डेयरी विकास को अन्य राज्यों की अपेक्षा ज्यादा विकास हुआ है। साथ ही प्रदेश में दुग्ध महासंघ की स्थापना, गौसेवा आयोग एवं किसान कल्याण परिषद की स्थापना से पशु पालकों एवं कृषको तथा दुग्ध व्यवसायियों को सामाजिक, आर्थिक उन्नति करने में उचित मदद प्राप्त हुई हैं। (पशुधन विकास की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर 2001–2018) शासन द्वारा पशुधन विकास नीति तो बनाई गई परंतु प्रदेश की गौशाला एवं डेयरी के लिए उचित नीति नहीं बनाई गई। जिससे प्रदेश में गौशालाओं की स्थिति अत्यंत कमजोर है वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर कृषि पर आधारित डेयरी विकास पर नई नीति बनाई जाए जिससे डेयरी व्यवसाय का उचित विकास हो सके साथ ही गौशालाओं का आर्थिक रूप से सुदृढीकरण किया जा सके।

छत्तीसगढ़ अंचल में धान फसल पद्धति ही अपनाई जाती है। लेकिन यह देखा गया है कि अन्य परंपरागत फसलों के उत्पादन मात्र से ही यहां के किसानों का आर्थिक उत्थान संभव नहीं हैं। क्योंकि इस अंचल में सिंचाई संसाधनों के अभाव में धान उत्पादन लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकता ऐसी स्थिति में दुग्ध उत्पादन यहां के किसानों की आमदनी का एक उपयुक्त साधन हो सकता है। क्योंकि धान की फसल के उप उत्पादों का उपयोग पशुधन के चारे के रूप में किया जा सकता है तथा पशुओं से प्राप्त गोबर गोमूत्र का उपयोग वर्तमान स्थिति में सबसे उपयुक्त खाद एवं गोमूत्र से कीट नियंत्रक बनाकर खेती को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाया जा सकता है।

इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा वर्ष 2019 में नरवा, गरवा घुरवा एवं बाड़ी के रूप में एवं महत्वाकांक्षी शीर्षस्थ परियोजना को प्रदेश में शुरू किया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य गौवंश संरक्षण एवं संवर्धन गौशाला स्तर पर हो एवं किसानों एवं गौशालाओं को आर्थिक आय से सुदृढ़ बनाना है धान आधारित फसलोत्पादन एवं दुग्ध उत्पादन दोनों एक दूसरे के पूरक व्यवसाय है। जिसे अपनाकर इस अंचल के कृषकों एवं गौशालाएं अपनी आर्थिक स्थिति को सबल बना सकते है। दुग्ध व्यवसाय को कृषि फसल पद्धति के आधार पर निम्नलिखित परियोजनाओं पर आधारित डेयरी विकास नीति का निर्धारण किया जाएं –

1. कृषि एवं डेयरी व्यवसाय सहकारिता कार्यक्रम ।
2. पशु पालन पर आधारित परियोजनाएं –

जैसे–

a) प्रजनन पर आधारित परियोजनाएं ।
b) देशी नस्लों की उत्पादन क्षमता बढ़ाना।
c) उन्नत किस्म के प्रजाति के जननदृव्य का उत्पादन कर संकरीकरण।
d) चारा उत्पादन एवं पशु आहार प्रबंधन कार्यक्रम।
e) चलित पशु चिकित्सालय परियोजना।
f) पशु प्रशिक्षण कार्यक्रम।
g) पशु प्रदर्शनी एवं मेले का आयोजन आदि।

3. दुग्ध उत्पादन एवं संसाधन पर अनुसंधान –

a) उचित पशु जाति का चयन।
b) पोषण प्रबंधन ।
c) फसलोत्पादन की परिस्थितियों की डेयरी व्यवसाय पर आधारित समन्वयक परियोजना

4. पशुपालकों एवं दूध उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम ।
5. दूध संकलन एवं उचित मूल्य निर्धारण कार्यक्रम।
6. पुरानी दुग्ध उत्पादन तकनीकी का नवीनीकरण।
7. लघु स्तर पर स्थित ग्रहों का निर्माण ।
8. गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम।
9. सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन, भारवाही एवं चरवाही प्रथा की वैकल्पिक पद्धति की खोज।

प्रजनन नीति

गायों को वर्तमान प्रजनन नीति के अनुसार निश्चित नस्ल की गायों को दूध तथा बैलों को भारवाहन क्षमता के लिए अनुवांशिक आंकलन के आधार पर विकसित किया जाता है। तथा बहुत कम दूध देने वाली नस्ल की देशी गायों का अधिक दूध देने वाली देशी नस्लों से संकरण कराके संकर गायों के अन्त प्रजनन द्वारा स्थायित्व प्रदान किया जा सकता हैं। प्रजनन नीति का मुख्य उद्देश्य यह है कि सन् 2000 में 8 करोड़ टन दूध उत्पादन करना था। अच्छी नस्ल के बढ़िया सांड के वीर्य को संकलित कर उसे कृत्रिम गर्भाधान के लिए वितरित करने की सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाए तथा दुधारू पशुओं के लिए राष्ट्रीय समूह बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है यदि इसको सुचारु रुप से राज्य स्तर पर लागू किया जाए तो दूध उत्पादन और अधिक बढ़ सकता हैं। छत्तीसगढ़ में लगभग **80%** देशी नस्ल है यदि उन्नत किस्म के सांडों का उपयोग कर हिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कराया जाय तो छ.ग. में अन्य राज्यों की भांति दूध उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।

तालिका क्रमांक – 01
राज्य में प्रस्तावित गोवंश एवं भैसों की जनसंख्या तथा विकास क्रम

(लाख में)

विवरण	10वीं योजना के अंत में (2006) (उपलब्ध)	11वीं योजना के अंत में (2011) (लक्षित)	12वीं योजना के अंत में (2012) (लक्षित)	13वीं योजना के अंत में (2021) (लक्षित)
गैर वर्णात्मक गोवंश	71.06	69.30	67.59	65.92
संकर (प्रजनन) पशु/सुधार	17.76	26.09	38.33	56.32

देशी नस्ल				
कुल गोवंश	88.82	95.39	105.92	122.24
गैर वर्णात्मक भैंस	14.36	14.01	13.6	13.31
वर्गीकृत भैंस	9.60	2.14	2.86	3.82
कुल भैंस	15.96	16.15	16.52	17.13

Source – पशु विभाग

1. गैर वर्णात्मक मवेशियों (सांडो) में लगभग 0.5% की वृद्धि हो जायेगी।
2. प्रजनित पशु/स्वदेशी सांडो में सालाना 0.6% की वृद्धि होगी।
3. गैर वर्गीकृत भैंसो में सालाना 0.5% की वृद्धि होगी।
4. वर्गीकृत भैंसो में सालाना 0.8% की वृद्धि हो जायेगी।

शंकर सांड उत्पादन कार्यक्रम

प्रारंभ में प्रचलित सांड उत्पन्न प्रजनन फार्म स्थापित किए गए तथा सांडों का चयन उनकी शारीरिक रचना तथा दूध की उत्पादन क्षमता के आधार पर ऐसे चयनित सांडों का उपयोग प्राकृतिक एवं कृत्रिम प्रजनन के लिए किया गया हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं में महत्वपूर्ण स्वदेशी नस्लों एवं कुछ विदेशी नस्लों के प्रजनन फार्म इन नस्लो सांडों का संतति परीक्षण करने के लिए स्थापित किए गए। इस कार्यक्रम में 300 प्रजनन योग्य मादाओं पर 10 सांडों का संतति परीक्षण किया गया जिसमें 10 से 12 मादा संतति का आकार के आधार पर नहीं था।

संगठित गौशालाओं के सहयोग से उपलब्ध समूह द्वारा भी सांडों की वांछित संख्या उत्पन्न नहीं की जा सकती है इसलिए किसानों की प्रजनन योग्य गायों को भी इस कार्यक्रम में शामिल करना होगा। भ्रूण प्रत्यारोपण प्रौद्योगिकी क्षरा अनुवांशिक विकास में वृद्धि तथा पीढ़ी अंतराल कम किया जा सकता हैं। इससे प्रतिवर्ष लगभग दो से तीन प्रति लीटर तक दूध उत्पादन बढ़ाया जा सकता हैं। एवं कुल ग्रोथ दर पंचवर्षीय योजना **2006** से **13**वीं पंचवर्षीय योजना तक लगभग 6.5% की दर से दूध उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।

(Table - II)

तालिका क्रमांक – 02

विकासक्रम एवं लक्षित कार्य

विवरण	10वीं योजना के अंत में (2006) (उपलब्ध)	वर्तमान स्तर (2009)	11वीं योजना के अंत में (2011) (लक्षित)	12वीं योजना के अंत में (2016) (लक्षित)	13वीं योजना के अंत में (2021) (लक्षित)
दुग्ध उत्पादन (लाख/लीटर/दिन)	8.31	9.09	11.38	15.59	21.35
प्रति गौवंश द्वारा (ग्राम प्रतिदिन)	112	119	153	210	288
वार्षिक वृद्धि दर :	4.18	3.13	6.5	6.5	6.5

Source – पेरापेट प्रशिक्षण पुस्तिका

1. ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2006 की 10वीं पंचवर्षीय योजना में दुग्ध का उत्पादन 8.31 लाख लीटर प्रति दिन था जो कि 2021 की 13वीं पंचवर्षीय योजना तक बढ़कर 21.35 लाख लीटर प्रतिदिन हो जायेगी।
2. प्रति मवेशी दुग्ध उत्पादन 112 ग्राम/दिन से बढकर 288 ग्राम/दिन हो जायेगी। (157%) की वृद्धि ।
3. राष्ट्रीय : प्रति मवेशी दुग्ध उत्पादन 252 ग्राम प्रतिदिन ।

चारा उत्पादन एवं पशु आहार प्रबंधन कार्यक्रम

ग्रामीण स्तर पर अच्छे किस्म के चारे का उत्पादन किसान नहीं कर पाते हैं। इसके लिए चारा अनुसंधान द्वारा विभिन्न प्रकार के चारे की प्रजातियां निकाली गई है। उन्है किसानों के खेतों तक पहुंचाकर उन्नत तरीके से उंगा कर पशुओं को उपलब्ध कराया जाए, जिससे ग्रामीण स्तर पर एवं गौशाला स्तर पर दूध उत्पादन को बढ़ाया जा सके । चारा उत्पादन हेतु प्रयास सरकारी परियोजनाओं के अंतर्गत चारा उत्पादन कार्यक्रम को भी बढ़ाया जाए। जिससे किसानों और डेयरी व्यवसायियों को तथा गौशाला की आर्थिक स्थिति को सुधारने में अधिक बल मिलेगा।

(Table - III)

तालिका क्रमांक 03

चारा उत्पादन एवं पशु आहार की वर्तमान स्थिति

चारें का प्रकार	आवश्कता	उपलब्धता	चारा एवं आहार की कमी	
			कुल कमी	कमी का प्रतिशत
सूखा चारा	122.69	96.05	(-) 26.64	21.71
हरा चारा	368.09	58.42	(-) 309.67	84.13
पौधे	36.471	12.16	(-)24.31	66.66

Source – Brithal P.S. and Raju ss. (2006) microeconomic dimentianing Vhi & livestock souce by chhatiisgarh

1. फिर भी यह देखा जा सकता है कि राज्य में मुख्य रूप से चारा (सूखा चारा) में धान बड़े स्त्रोतों में उपलब्ध होता है और हरे चारे की आपूर्ति का बड़ा हिस्सा जंगलों और गोदामों से आता है।
2. पशुओं की नियमित स्थायी चराई के लिए राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 13% हिस्सा चारागाह के रूप में उपलब्ध है।

चलित पशु चिकित्सा परियोजना

वर्तमान में पशु चिकित्सालय ग्रामीण अंचल से दूर है जिससे पशुपालकों को पशु चिकित्सा में अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यदि किसानों के पशु बीमार होते है तो पशु चिकित्सक से संपर्क करने में देर हो जाती है एवं पशु की मृत्यु हो जाती है जिससे पशुपालकों को आर्थिक नुकसान बहुत होता है समय–समय पर सरकार द्वारा कई प्रकार की पशु चिकित्सा परियोजनाएं शुरू की गई परंतु किसानों तक नहीं पहुंच पाती है। एक सर्वेक्षण से पता चला है कि शासन द्वारा चलाई जाने वाली पशु चिकित्सा सुविधाएं किसानों तक नहीं पहुंच पाती है इसका मुख्य कारण पशु चिकित्सा की व्यवस्था में कमी। आंतरिक विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं हो पाता है एवं चिकित्सकों एवं अधिकारियों का अपेक्षापूर्ण व्यवहार भी इसके लिए जिम्मेदार है । साथ ही पशु चिकित्सकों प्रति पशु संख्या लगभग (लगभग **8000** पशु पर एक चिकित्सक) वर्तमान में **32000** पशुओं पर एक चिकित्सक है जो कुल ¼ प्रतिशत की कमी होने को पशु कारण उनकी उपलब्धता नही होना भी मुख्य कारण है अतः पशुओं की उचित चिकित्सा तब हो सकती है जब तक पशुपालकों को उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए एवं पशु चिकित्सा से होने वाले लाभ से अवगत कराया जाए और पशु चिकित्सा की जानकारी प्रदान की जाए । यदि सरकार द्वारा चलित पशु चिकित्सा परियोजना को गांव गांव स्तर पर चालू किया जाए तो दुधारू पशुओं को मरने से बचाया जा सकता है एवं दूध उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है।

(Table - IV) A=B
तालिका क्रमांक 04
(A)
वर्तमान में छ.ग. राज्य में पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाओं की स्थिति

क्रमांक	वर्तमान में पशु चिकित्सों की उपलब्धता	भारत सरकार के मानदण्ड की अनुसार स्थिति	राज्य में पशु चिकित्सों की स्थिति	
			स्वीकृत पद	deh (Deficit)
1	क्षेत्रीय पशु चिकित्सक	2990	595	2395
2	Paravets	2095	1829	266

तालिका क्रमांक 04
(B)
पशु चिकित्सलायों की स्थिति

क्रमांक	राज्य में पशु चिकित्सक संस्थान	उपलब्ध	अपेक्षित	deh (Deficit)
1	पशु अस्पताल	208	593	पशु अस्पताल
2	पशु चिकित्सा औषधालय	738	1848	पशु चिकित्सा औषधालय
3	Poly Clinics	Nil	कुल 36–1 राज्य Polyclinics	
4	नैदानिक प्रयोगशाला	7	Only one DI Lab in State	

Source – C.G. livestock development agency (2008)

पशु पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम

यह अनुभव किया गया है कि सरकार द्वारा चलाए जाने वाले पशु पालन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रभाव कम होता हैं, क्योंकि इन कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार उचित ढंग से नहीं हो पाता है साथ ही जो प्रशिक्षण दिए जाते है उनकी पश्चातवर्ती देखरेख एवं अनुपालन नहीं किया जाता है जिससे प्रशिक्षण का सही लाभ नहीं मिल पाता है सर्वेक्षण से यह पता चला है कि जो प्रशिक्षण किसानों एवं पशुपालकों को दिया जाता है उसका पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है। इस कारण आधुनिक डेयरी फार्म प्रबंधन एवं डेयरी उत्पादन का विकास नहीं हो पा रहा हैं। अतः जब तक सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों का पूर्ण मूल्यांकन नहीं किया जाता तब तक इस प्रकार की परियोजनाओं का लाभ नही मिल सकता। यदि सरकार द्वारा या सहकारी संस्थाओं द्वारा आधुनिक डेयरी फार्म, प्रबंधन तथा आदर्श गौपालन एवं गौशाला प्रबंधन ग्रामीण स्तर पर किया जाए तभी डेयरी विकास हो सकता है दूध उत्पादन को बढ़ाना है तो किसानों को समय–समय पर प्रशिक्षित किया जाए उन्है डेयरी उत्पादन एवं प्रसंस्करण की नई तकनीकी से अवगत कराया जाए, ऐसे क्षेत्र जो दूध उत्पादन में कमजोर है वहां सही तरीके से लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाए तो निश्चित ही दूध उत्पादन बढ़ाया जा सकता हैं।

पशु प्रदर्शनी एवं पशु मेलों का आयोजन

पशुपालकों के प्रोत्साहन हेतु समय–समय आयोजन होने से उत्पादन को बढ़ावा मिलता हैं। इस

प्रकार के आयोजन से दूध उत्पादकों को प्रोत्साहन मिलता है, एवं डेयरी व्यवसाय के प्रति जागरूकता आती है इससे दूध व्यवसायी प्रभावित होकर अपने व्यवसाय को बढ़ाने की चेष्टा करता है साथ ही आधुनिक तरीके से अपने व्यवसाय को बढ़ाता है। इस प्रकार के आयोजनों से दूध उत्पादन की नवीनतम जानकारी पशु पालकों को मिलती है, जैसे कि पशु का रखरखाव पशु चिकित्सा आहार प्रबंधन पशुओं का चयन, दोहन की विधियां कृत्रिम गर्भाधान पशुशाला का रखरखाव, नवीनतम प्रजनन विधियां, गुणवत्ता संबंधी जानकारी आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। अतः पशु प्रदर्शनी एवं मेलों का आयोजन कर कार्यक्रम एवं अन्य सहकारी सेवा संस्थानों द्वारा चलाया जाये, यह कहा जा सकता है कि दूध उत्पादन में वृद्धि सरलता से की जा सकती है।

कृषि एवं डेयरी व्यवसाय सहकारिता कार्यक्रम

कृषि एवं डेयरी व्यवसाय सहकारिता कार्यक्रम यदि गैर सरकारी संस्थाएं द्वारा चलाया जाए तो दूध उत्पादन को बहुत संबल मिल सकता हैं। कृषि के साथ–साथ यदि डेयरी व्यवसाय कार्यक्रम को किसान अपनाता है तो निश्चित ही दूध उत्पादन को बढ़ावा मिल सकता है। वर्तमान में हुए कुछ अनुसंधान से यह पता चला है कि यदि किसान खेती के साथ डेयरी व्यवसाय करता है तो उसे इसका लाभ होता हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान परिषद द्वारा विभिन्न प्रकार के मॉडल इस योजना से संबंधित बनाए गए है जिससे यह पता चलता है कि किसानों को अधिकतम लाभ प्राप्त होता हैं। यदि बनाये गये मॉडलों को सरकार द्वारा या गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित किया जाए तो निश्चित ही दूध के उत्पादन में दूगनी बढ़ोतरी हो सकती है। इस प्रकार के मॉडल सरलता से राष्ट्रीय संस्थाओं में उपलब्ध है जिसे प्रतिपादित करने में भी विशेष कठिनाई नहीं होती। इसे आसानी से ग्रामीण स्तर पर लागू कर दूध उत्पादन के साथ–साथ किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है।

(केरल मॉडल)

पशु पालकों एवं दूध उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम

सरकारी एवं निजी संस्थाओं के सुचारू रूप से कार्य न करने के कारण किसान इस योजना की ओर ध्यान नहीं देते है। यदि सहकारी एवं सरकारी संस्था को जो लाभ होता है उसका कुछ भाग (लगभग 5% तक) दूध उत्पादकों एवं डेयरी व्यवसायियों को वितरित कर दिया जाए तो इससे उनको अपने व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिलेगी साथ ही दूध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। यदि इस प्रकार का कार्यक्रम व्यवस्थित चलाया जाए तो पशु पालकों एवं दुग्ध व्यवसायियों को प्रोत्साहन मिलेगा। यदि इस योजना को लागू करने के लिए विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियां बनाई जाए एवं समय–समय पर नियंत्रण रखा जाए तो दूध उत्पादन को संबल मिलेगा इस प्रकार के व्यवसाय कुछ राज्य में है, जैसे –गुजरात, महाराष्ट्र एवं पंजाब। यदि इसे सुचारु रुप से अन्य राज्यों में भी लागू किया जाए तो अधिक दूध उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।

दुग्ध संकलन एवं उचित मूल्य निर्धारित कार्यक्रम

आज भी दूध संकलन की समस्या बनी हुई है। क्योंकि गांव में रहने वाले किसानों के द्वारा उत्पादित दूध के खरीददार नहीं है इसका मुख्य कारण सहकारी समितियों की कमी दूसरा दूध का उचित मूल्य न मिलना। यदि गांव स्तर पर छोटी–छोटी सहकारी समितियां बनाई जाए जो किसानों द्वारा उत्पादित दूध को उचित मूल्य पर क्रय कर सके। एवं इसके उत्पादन का सही मूल्य निर्धारण हो सके जिससे किसानों का दूध उत्पादन बढ़ाने में उत्साह वर्धन किया जा सकता हैं। इसके लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं को आगे आना होगा तथा उचित मूल्य निर्धारण नीति बनाने की आवश्यकता होगी साथ ही प्रोत्साहन नीति बनानी होगी, तभी दूध उत्पादन को बढ़ावा मिल सकता है। उचित मूल्य न मिलने के कारण किसान तथा पशु पालक निराश हो जाते है एवं कुछ समय बाद इस व्यवसाय को बंद कर देते है। इससे यह आशय निकलता है कि किसानों को दूध एवं दुग्ध पदार्थों, उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके तब ही किसान प्रोत्साहित होकर डेयरी व्यवसाय को बढ़ा सकेगा।

सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन

"दूध उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए" विषय पर किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि आज भी कई क्षेत्रों में कुछ सामाजिक कुरीतियां है, जैसे – बरवाही प्रथा और चरवाही प्रथा, अधिक मानदण्ड आदि जो कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आते है। बरवाही प्रथा में एक दिन का पूरा दूध ग्वाला को पशुपालक/किसानों द्वारा एक सप्ताह में दिया जाता है। जो कि एक सामाजिक बंधन है जबकि पशु पालकों का पूर्ण खर्च होता है । इसी कारण किसान उत्साहित न हो कर अपना व्यवसाय कभी–कभी बंद भी कर देता हैं। आज भी किसानों में चरवाही प्रथा है। जिससे किसानों को आर्थिक हानि होती है इसे बंद किया जाए तो दूध उत्पादन उन क्षेत्रों को दुगना किया जा सकता है। आज भी गांव में दूध बेचना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि गाय को पूज्यनीय (गौमाता) माना जाता है। जो इसका दूध बेचता है उसे गांव के मुखिया द्वारा आर्थिक दंड या फिर उसका बहिष्कार किया जाता हैं। इसके लिए सामाजिक जन जागरण की आवश्यकता है जिससे इस प्रथा पर नियंत्रण किया जा सकें।

उक्त कुरीतियों को दूर करने हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा अभियान चलाया जाना चाहिए तभी कुरीतियों को समूल दूर किया जा सकता है तभी दूध उत्पादन लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है । दूध उत्पादन हेतु बतायें गये इन दस बिंदुओं को अमल में लाने से दूध उत्पादन में 2 गुना बढ़ोतरी की जा सकती है तथा प्रत्येक नागरिक तक उचित मात्रा में दूध प्राप्त हो सकता है अभी तक जो 80 प्रतिशत दूध ग्रामीण अंचल से लाया जाता है वह एक व्यक्ति विशेष तक सीमित रहता है दूध संकलन व्यवस्था एवं गुणवत्ता नियंत्रण को प्रभावी रूप से सहकारी एवं गैर सहकारी संस्थाओं से मदद लेना अति आवश्यक हैं।

निष्कर्ष

उपरोक्त परियोजनाओं का उचित संचालन उचित डेयरी विकास की नई नीतियों को बनाने पर ही किया जा सकता है। एवं इससे सरकार की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इन योजनाओं को संचालित करने हेतु आर्थिक सहायता की अधिक आवश्यकता होती है राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ किसान आयोग एवं गौसेवा आयोग का गठन कर तो दिया गया है परंतु डेयरी विकास के लिए ऐसा कोई विशेष आयोग या परिषद का प्रावधान नहीं किया गया है। यदि हमें इस नवगठित राज्य में जो आज किशोरावस्था में है, ध्यान नहीं दिया गया तो प्रदेश अन्य प्रदेशों की भांति पिछड़ जाएगा। इसलिए आर्थिक विकास के वैकल्पिक कृषि डेयरी व्यवसाय पर अधिक ध्यान देना होगा, क्योंकि यह ऐसा व्यवसाय है जो अकाल, प्राकृतिक आपदा, भूखमरी, बेरोजगारी, अल्पवर्षा, अतिवृष्टि एवं निर्धनता को दूर करने में सक्षम हैं। इसलिए इस व्यवसाय को विशेष दर्जा देकर प्रदेश एवं गौशालाओं की आर्थिक उन्नति की जा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *डॉ. पी. एल. चौधरी, (2006) छ.ग. राज्य में दुग्ध उत्पादन के नीतिगत पहलू, छ.ग.राज्य में व्यवसायिक चुनौतियां, पैरापेट प्रशिक्षण पुस्तिका*
2. *डॉ. पी. एल. चौधरी, (2016) छ.ग. में चारा उत्पादन की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य में संभवानाएं , चारा उत्पादन एवं प्रबंधन*
3. *पी. एल. चौधरी, (2001) दुग्ध व्यवसाय के लिए नीति निर्धारण, छ.ग. खेती कृषि विश्वविद्यालय रायपुर (छ. ग.)*
4. *गोसम्पदा, (2019) पशु जनगणना वर्ष 2018 वर्तमान स्थिति का आंकलन एवं परिदृश्य*
5. *P. L. CHOUDHARY (2006) Policy issues for chattisgharh dairy development, it's animal health and milk production book.*
6. *C.G. Livestock development agency (2008), action plan and recommendation for inhancement in livestocks.*